भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2953
जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 'यूटिलिटी सर्विस डक्ट'

2953. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र के हिम्मतनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के विस्तार के दौरान 'यूटिलिटी सर्विस डक्ट' (जैसे जल निकासी, पानी की पाइपलाइन और बरसाती पानी प्रबंधन) के उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार हिम्मतनगर पालिका की मांग के अनुसार मोतीपुरा क्रास रोड जंक्शन, पॉलिटेक्निक क्रास रोड और सहकारीजीन क्रास रोड पर क्रमशः दो 'यूटिलिटी सर्विस डक्ट' उपलब्ध कराने का है;
(ग) यदि हां, तो उक्त डक्ट उपलब्ध कराने की समय-सीमा क्या है और इसके लिए कितने बजट की आवश्यकता है; और
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाने के लिए उचित कदम उठाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) यूटिलिटी कॉरिडोर सामान्यतः एनएच मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के सबसे किनारे पर प्रदान किया जाता है। तथापि, आरओडब्ल्यू की विवशता के मामले में, यूटिलिटी एजेंसियों द्वारा डक्ट या वैकल्पिक संरेखण की व्यवस्था की खोज की जाती है। वर्तमान मामले में, मौजूदा यूटिलिटीज को स्थानांतरित करने/समायोजित करने के लिए, एनएच-48 के शामलाजी - हिम्मतनगर-मोटाचिलोडा खंड में आरओडब्ल्यू के सबसे किनारे पर यथासंभव स्थान निर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) मौजूदा यूटिलिटीज को पार करने के लिए, मोतीपुरा क्रॉस रोड जंक्शन, पॉलिटेक्निक क्रॉस रोड और सहकारी जो क्रॉस रोड पर नलिकाओं (डक्ट) का प्रावधान किया गया है, जो 25 जून तक पूरा होने वाले सिविल अनुबंध के भाग के रूप में है।

*****